

आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दशा एवं दिशा का आलोचनात्मक अध्ययन वर्तमान शिक्षा की दशा एवं दिशा

डॉ परमेश्वर कुमार पाण्डेय

भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का गौरवशाली इतिहास पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के गुरु आचार्य एवं शिष्य आदर्श के रूप में स्थापित रहे हैं। भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। गुरु का महत्व समस्त कीमती वस्तुओं एवं पदों से उपर था। अवतारी महापुरुषों तथा ईश्वर ने भी गुरु को अपने से उपर बताया है। यह प्राचीन गौरव आज अतीत का विषय हो चुका है।

वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

1. प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा
3. उच्चशिक्षा

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को दो वर्गों में बाटा जा सकता है—सरकार द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था जिसमें शिक्षकों को वेतन दिया जाता है तथा छात्र/छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा छात्र/छात्रों को प्रलोभन दिया जाता है।

दूसरे वर्ग में वे स्कूल या विधालय जिसमें सरकार द्वारा केवल स्कूल खोलने की मान्यता दी जाती है जिसमें काई भी व्यवित जो साधन सम्पन्न हो विधालय खोल सकता है। सरकार द्वारा इन विधालयों के शिक्षकों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। ये विधालय प्राइवेट विधालय के नाम से प्रसिद्ध हैं; जिसमें इसे चलाने के लिए

छात्र/छात्राओं से मोटी शुल्क ली जाती है। इन विधालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की स्थिति मजदूरों से भी बद्तर होती है। इन प्राइवेट विधालयों में स्कालर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देने की व्यवस्था सरकार करती है लेकिन अध्यापकों को देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं होता है। इन शिक्षकों को वेतन के नाम पर कुछ पैसे विधालय चलाने वाले प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है। उनकी आय का स्रोत बच्चों द्वारा दिया गया शुल्क होता है।

दूसरे स्तर पर माध्यमिक विधालय है। इसमें कुछ राजकीय विधालय कुछ केन्द्रीय विधालय कुछ नवोदय विधालय तथा अधिकांश मात्रा में प्राइवेट विधालय है। प्राइवेट विधालयों को पुराने सत्र के आधार पर सरकार द्वारा अनुदान की सूची में लिया जाता है।

राजकीय विधालय केन्द्रीय विधालय तथा सरकार द्वारा अनुदानित विधालय के अध्यापकों का वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है। प्राइवेट विधालय को वेतन उसे संचालित करने वाले प्रबन्ध समितियों द्वारा दिया जाता है। यह वेतन सरकारी अध्यापकों की तुलना में काफी कम होता है।

तृतीय स्तर पर उच्चशिक्षा की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था है— संघ सूची; राज्य सूची तथा समवर्ती सूची।

*प्राचार्य, जी.डी.एस.बी.पी.जी. कालेज डेरापुर, कानपुर देहात।

Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

शिक्षा न तो राज्य सूची में है न ही संघ सूची में बल्कि इसकी व्यवस्था समवर्ती सूची में की गयी है। अतः केन्द्र एवं राज्य इसे एक दूसरे पर टालते रहते हैं।

भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं राज्यों में राज्यविश्व विद्यालयों की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय संचालित होते हैं। राज्य विश्वविद्यालय में भी सरकारी एवं गैर सरकारी की व्यवस्था है। सरकारी विश्वविद्यालय में भी कुछ लोगों को सरकार द्वारा वेतन प्रदान किया जाता है तो कुछ कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न मदों से वेतन दिया जाता है जो प्राइवेट तथा अस्थायी होते हैं।

तृतीय स्तर की शिक्षा में सरकार ने एक स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को मान्यता दे दिया है जिसका संचालन सांसदों विधायकों मन्त्रियों नौकरशाहों तथा देश की पूँजीपतियों द्वारा किया जाता है। इन पूँजीपतियों की सरकार पर मजबूत पकड़ हाती है तथा कोई भी कानून इनके हितों के विरुद्ध नहीं बन पाता। इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में देश के बुद्धिजीवी इमानदार नौकरी करते हैं जिनके पास अपना रोजगार करने के लिए पैसा नहीं होता तथा सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत नहीं दे सकते। इन नवयुवकों का भरपूर शोषण किया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन महाविद्यालयों के प्राचार्य जो महाविद्यालय के मुखिया होते हैं उनकी सेवा की कोई नियमावली नहीं है। इन महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा स्कॉलरशिप तथा शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है लेकिन अध्यापकों तथा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास धन नहीं होता। शिक्षा की उपर्युक्त तीन श्रेणियों में जो विसंगतियाँ हैं सरकार द्वारा इसका कोई

समाधान नहीं किया जाता या ये कही लीजिए कि सरकार समाधान करना ही नहीं चाहती। शिक्षा की अत्यन्त दयनीय दशा है। सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा कोठ रोग के समान है जिसमें पढ़ने वाले छात्र/छात्राएं कोढ़ी होकर निकलते हैं जो देश के उपर भार बनते हैं। प्राइवेट शिक्षक परिश्रम तो करते हैं परन्तु आगे उन शिक्षकों का क्या भविष्य होगा वे इस साल काम कर रहे हैं अगले वर्ष शिक्षक रहेंगे या विद्यालय से निकाल दिये जायेंगे। ख्याल नहीं जानते। इन शिक्षकों का जिनको अपने भविष्य का पता नहीं है किस प्रकार छात्रों के भविष्य का निर्माण करेंगे।

माध्यमिक शिक्षा जो सरकारी तथा प्राइवेट दो वर्गों में बटी है अधिकांश विद्यालय के छात्र/छात्राएं नकल के सहारे है। प्राइवेट विद्यालय केवल अपना रिजल्ट सुधारने में लगे हैं गुणवत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। सी बी एस सी बोर्ड द्वारा शिक्षा में सुधार का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसमें भी प्राइवेट विद्यालय संचालक इसे अपनी दुकान बनाने में लगे हैं।

सबसे अधिक दुर्दशा उच्चशिक्षा की है जिसमें केवल नकल का बोलबाला है। विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नगण्य है। वास्तविकता यह है कि ये महाविद्यालय केवल डिग्री एवं सर्टीफिकेट बाटने की मशीन बन कर रह गये हैं।

समाधान—सुझाव

1. देश के बजट में शिक्षा पर 35 प्रतिशत व्यय किया जाय।
2. शिक्षा को संघ सूची अथवा राज्य सूची में शामिल किया जाय।
3. सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों को बन्द कर दिया जाय। प्राथमिक रस्तर पर गाँव के ग्राम प्रधान को प्राथमिक विद्यालय के भवनों की सुरक्षा तथा एक प्रधानाध्यापक को

नियुक्त किया जाय। उसके लिए न्यूनतम योग्यता तय होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक को मानक के अनुसार वेतन दिया जाय। गाँव में से ही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो तथा विद्यार्थियों से उचित शुल्क लिया जाय जिसपर ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक का नियन्त्रण हो। शिक्षकों का वेतन सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। सरकार द्वारा पचास प्रतिशत वेतन अपने निधि से तथा पचास प्रतिशत शुल्क से होना चाहिए। शुल्क के बचत भाग को विद्यालय भवन के विकास में खर्च किया जाय। अध्यापक द्वारा लापरवाही की स्थिति में प्रधानाध्यापक की संस्तुति पर ग्राम प्रधान द्वारा दण्डित किया जा सके।

4. कुटीर उद्योग को भी इस स्तर पर सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्तर पर विकसित किया जा सकता है।
5. जिस छात्र की आर्थिक स्थिति खराब है ग्राम प्रधान द्वारा संस्तुति की जा सकती है जिसके शुल्क में रियायत की जा सकती है।
6. सरकार द्वारा कोई स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति न दिया जाय बल्कि इस धन को रोजगार उत्पन्न करने पर व्यय किया जाय।

माध्यमिक स्तर पर सभी प्रकार के बोर्ड में एकता हो। पाठ्यक्रम समान हो। सरकार द्वारा जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय की संख्या एवं स्थान निश्चित कर लिया जाय तथा देश के पूँजीपतियों को विद्यालय खोलने के लिए आमन्त्रित किया जाय। सरकार द्वारा मानक निश्चित किया जाय। पूँजीपतियों द्वारा विद्यालय खोलने के बाद एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य होगा जिसका वेतन सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा तथा उसे सरकार अपनी निधि से

देगी। शेष शिक्षक सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति मण्डल द्वारा होगा जिसमें प्रबन्ध समिति भी शामिल होगी। विद्यालय में पूर्ण पारदर्शिता होगी। शुल्क का 70 प्रतिशत अध्यापकों के वेतन के मद में होगा जो सरकार के खजाने में जायेगा तथा सरकार उससे अध्यापकों को वेतन प्रदान करेगी। 30 प्रतिशत शुल्क प्रबन्ध समिति अपने विद्यालय के रखरखाव में खर्च करेगी। तृतीय स्तर पर उच्चशिक्षा जो समाज की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करता है। वर्तमान उच्चशिक्षा की व्यवस्था दोषपूर्ण है अतः उसे समाप्त कर नवीन दिशा तय की जायेगी।

देश में जितने भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की आवश्यकता है इसका निर्धारण किया जायेगा। जो उच्चशिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसे ही उच्चशिक्षा दी जाय उसके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की है सारे पैसे इकट्ठा कर उसको शत-प्रतिशत रोजगार दिया जाय। वर्तमान विद्यालय भवनों को तथा जितने की आवश्यकता हो उसे इच्छुक पूँजीपतियों द्वारा खोलवाया जाय। एक प्राचार्य की नियुक्ति हो जिसका उचित मानक के अनुसार वेतन सरकार द्वारा दिया जाय यह सरकार का अपना व्यक्ति होगा। शेष अध्यापकों की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित चयन समिति द्वारा किया जाय। प्राचार्य भी इस नियुक्ति मण्डल के सदस्य होंगे। सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण किया जाय। शुल्क का 70 प्रतिशत भाग सरकारी खजाने में जमा किया जायेगा। 30 प्रतिशत हिस्सा प्रबन्ध समिति द्वारा अपने अनुसार व्यय किया जायेगा जिसका उस लेखा जोखा देना होगा। अध्यापकों का वेतन सरकार द्वारा दिया जायेगा। कमजोर छात्र/छात्राओं जो अर्थिक रूप से निर्धन हैं तथा पढ़ने में उत्तम हैं सरकार द्वारा शुल्क

मेरियायत दी जायेगी। किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप नहीं दिया जायेगा। उच्चशिक्षा प्राप्त छात्र/छात्राओं को शत प्रतिशत रोजगार दिया जायेगा। गुरुओं को प्राचीन परम्परा के अनुसार सम्मान दिया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था स्थापित कर देश के नवीन भविष्य का निर्माण किया जा सकता

है तथा गुरुकुल की परम्परा स्थापित कर भारत विश्व गुरु बन सकता है। शिक्षा रूपी कारखाने में मानव निर्मित होता है अतः इसके निर्माण कर्ता को आदर्श मानकर पहले उसके भविष्य का निर्माण किया जाय देश का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल होगा।

जय हिन्द—जय भारत